



## फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी

### प्रलिस के लयः

फेस रिकॉग्निशन, आर्टफिशियल इंटेलजेंस, डेटा सुरक्षा कानून

### मेन्स के लयः

फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी : आवश्यकता एवं चुनौतियाँ

## चरचा में क्यों?

तीन वर्षों की वलंबता के बाद, वर्ष 2022 से यात्री देश के चार हवाई अड्डों (वाराणसी, पुणे, कोलकाता और वजियवाडा) पर अपने बोर्डिंग पास के रूप में 'फेस स्कैन' (Face Scan) का उपयोग कर सकेंगे।

## प्रमुख बडि

### ■ फेशियल रिकॉग्निशन (Facial Recognition):

- यह एक **बायोमेट्रिक तकनीक** है जो कसिी वयक्तकी पहचान और वयक्तियों के बीच अंतर करने के लयि चेहरे की वशिषिट वशिषताओं का उपयोग करती है।
  - लगभग छह दशकों में **स्कनि पैटर्न को पहचानने से लेकर चेहरे की 3D आकृति** को बनाने तक यह प्रणाली कई मायनों में वकिसति हुई है।
- **ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन ससि्टम (Automated Facial Recognition System- AFRS)** वयक्तियों के चेहरों की छवियों और वीडियो के व्यापक डेटाबेस के आधार पर कार्य करती है। इसमें मौजूद डेटाबेस में उपलब्ध छवियों से मलान करके वयक्तकी पहचान की जाती है।
- सीसीटीवी फुटेज़ से प्राप्त अज्जात वयक्तके चेहरे के पैटर्न की तुलना **आर्टफिशियल इंटेलजेंस** तकनीक की सहायता से डेटाबेस में उपलब्ध पैटर्न से की जाती है।

### ■ कार्यप्रणाली:

- प्रारंभिक स्तर पर **फेस रिकॉग्निशन प्रणाली में कैमरे द्वारा चेहरे और उसकी वशिषताओं को कैचर कयिा जाता है।** पुनः वभिनिन प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग कर उन वशिषताओं का पुनर्निमाण कयिा जाता है।
- **चेहरे और उनकी वशिषताओं को एक साथ एक डेटाबेस में संगृहीत कयिा जाता है** तथा इसे कसिी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत कयिा जा सकता है। इसका उपयोग बैंकिंग सेवा, सुरक्षा उद्देश्यों की पूर्ताइत्यादि में कयिा जा सकता है।

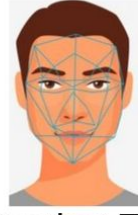
# How Facial Recognition Systems Work

1



Capturing and scanning

2



Extracting Facial Data

3



Comparing database

4



Matching and Identifying

## ■ आवश्यकता:

### ○ प्रमाणीकरण:

- इसे प्रमाणिकता एवं पहचान के लिये उपयोग में लाया जाता है एवं इसकी सफलता दर लगभग 75% है।

### ○ फोर्स मल्टीप्लायर:

- भारत में प्रति एक लाख नागरिकों पर 144 पुलिसकर्मी हैं। अतः फेस रिकॉग्निशन प्रणाली यहाँ बल गुणक (Force Multiplier) के रूप में कार्य कर सकती है क्योंकि इसे न तो अधिक कार्यबल की आवश्यकता है और न ही नियमिता उन्नयन की।
- यह तकनीक वर्तमान जनशक्ति/कार्यबल के साथ मलिकर एक गेम चेंजर के रूप में कार्य कर सकती है।

## ■ चुनौतियाँ:

### ○ अवसंरचनात्मक लागत:

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बगि डेटा जैसी प्रौद्योगिकियों का क्रयान्वयन महंगा होता है।
- संगृहीत सूचनाओं की मात्रा बहुत बड़ी होती है और इसके लिये विशाल नेटवर्क एवं डेटाभंडारण सुविधा की आवश्यकता होती है जो वर्तमान में भारत के पास उपलब्ध नहीं है।

### ○ गोपनीयता का उल्लंघन:

- हालाँकि सरकार डेटा गोपनीयता व्यवस्था जैसे कानूनी ढाँचे के माध्यम से गोपनीयता के मुद्दे को संबोधित करने की योजना बना रही है, लेकिन इस प्रकार की तकनीक के उपयोग से प्राप्त होने वाले उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, यह आपसी हितों में टकराव उत्पन्न कर सकता है।

### ○ विश्वसनीयता और प्रमाणिकता:

- चूँकि एकत्र किये गए डेटा का उपयोग आपराधिक मुकदमे के दौरान न्यायालय में किया जा सकता है, इसलिये मानकों और प्रक्रिया के साथ-साथ डेटा की विश्वसनीयता एवं स्वीकार्यता को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

### ○ डेटा सुरक्षा कानून की अनुपस्थिति:

- **डेटा सुरक्षा कानून** (Data Protection Laws) की अनुपस्थिति में FRT सिस्टम, जो उपयोगकर्ता द्वारा डेटा के संग्रह और भंडारण में आवश्यक सुरक्षा उपायों के लिये अनिवार्य होगा, भी चर्चा का विषय है।

### ○ अंतरनिहित चुनौतियाँ:

- समय के साथ चेहरे में परिवर्तन भी हो सकता है, यह भी चर्चा का विषय है।

## आगे की राह:

- वर्तमान डिजिटल युग में डेटा एक मूल्यवान संसाधन है जिसे अनयंत्रित या स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता। इस संदर्भ में भारत को एक मजबूत डेटा संरक्षण व्यवस्था स्थापित करनी चाहिये।
- अब समय आ गया है कि **व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2019** में आवश्यक परिवर्तन जाएँ। इन परिवर्तनों को सुनिश्चित करने हेतु इसमें आवश्यक सुधारों की आवश्यकता है। यह उपयोगकर्ता के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ उपयोगकर्ता की गोपनीयता पर भी ज़ोर देता है। इन अधिकारों को लागू करने हेतु एक गोपनीयता आयोग की स्थापना की जानी चाहिये।

- सरकार को सूचना के अधिकार को मज़बूत बनाने के साथ ही नागरिकों की नज़िता का भी सम्मान करना होगा। इसके अतिरिक्त पिछले दो से तीन वर्षों में हुए तकनीकी विकास को देखते हुए यह संबोधित करने की भी आवश्यकता है ये कानून तकनीकी विकास की सीमा को भी निर्धारित करते हैं।

## स्रोत: द हट्ट

## कृषि क्षेत्र के लिये ARCs

### प्रलम्बित के लिये:

भारतीय रज़िर्व बैंक, 'नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स'

### मेन्स के लिये:

परसिंपत्ता पुनर्निर्माण कंपनी, कृषि ऋण के लिये ARC की आवश्यकता

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में अग्रणी बैंकों द्वारा [कृषि क्षेत्र](#) में खराब ऋणों की वसूली में सुधार के लिये विशेष रूप से कृषि ऋणों के संग्रह और वसूली से निपटने हेतु एक [परसिंपत्ता पुनर्निर्माण कंपनी](#) (Asset Reconstruction Company- ARC) स्थापित करने के लिये योजना/रूपरेखा प्रस्तावित की गई है।

- बैंक द्वारा NPAs की चुनौती से निपटने के लिये सरकार समर्थित ARC की स्थापना के साथ ही इस अवधारणा को उद्योग और बैंकों के बीच स्वीकार्यता मिली है।
- [भारतीय बैंक संघ](#) के कुछ सदस्य बैंकों ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को वित्तीय संपत्तियों परतभूतकरण और पुनर्निर्माण और '[सकियोरिटाइज़ेशन एंड रकिंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोरसमेंट ऑफ सकियोरिटी इंटररेसट एक्ट](#)' (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act), 2002 की तरह कुछ सीमा तक कृषि भूमि पर कानून लाने की आवश्यकता है।

## प्रमुख बडि

- परसिंपत्ता पुनर्निर्माण कंपनी (ARC) के बारे में:**
  - उद्देश्य:** यह एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से '[नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स](#)' (Non Performing Assets- NPAs) खरीदता है ताकि वे अपनी बैलेंसशीट को स्वच्छ रख सकें।
    - यह बैंकों को सामान्य बैंकिंग गतिविधियों में ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। बैंकों द्वारा बकाएदारों पर अपना समय और प्रयास बर्बाद करने के बजाय वे ARC को अपना NPAs पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर बेच सकते हैं।
  - वधिकि आधार:** सरफेसी अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act, 2002) भारत में ARCs की स्थापना के लिये कानूनी आधार प्रदान करता है।
    - सरफेसी अधिनियम न्यायालयों के हस्तक्षेप के बिना गैर-नधिपदनकारी संपत्तियों के पुनर्निर्माण में मदद करता है। इस अधिनियम के तहत बड़ी संख्या में ARCs का गठन और उन्हें [भारतीय रज़िर्व बैंक](#) (RBI) के साथ पंजीकृत किया गया, जसिं ARCs को वनियमिति करने की शक्ति मिली है।
  - फंडगि:** ARC द्वारा अपनी फंडगि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, **बांड, डबिंचर और सकियूरिटी रसिीप्ट जारी की जा सकती हैं।**
  - 'नेशनल एसेट रकिंस्ट्रक्शन कंपनी लमिडिड' (NARCL):**
    - बजट 2021-22** में, ARC को राज्य के स्वामति वाले तथा नजिी क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, जसिमें सरकार की ओर से कोई इक्विटी योगदान नहीं दिया जाएगा।
    - ARC जो कि खराब परसिंपत्तियों के प्रबंधन और बकिरी के लिये परसिंपत्ता पुनर्निर्माण कंपनी होगी, 70 बडे खातों में 2-2.5 लाख करोड रुपए की परसिंपत्तियों का प्रबंधन करेगी।
    - इसे सरकार द्वारा स्थापित '[बैड बैंक](#)' (Bad Bank) का संस्करण माना जा रहा है।

## Why NPAs occur?



### ■ कृषि ऋण के लिये ARC की आवश्यकता:

- **बैंकों के NPAs:** [नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जून 2021](#) के अनुसार, कृषि क्षेत्र के लिये बैंकों का सकल एनपीए अनुपात 9.8% था, जबकि 2021 मार्च के अंत में उद्योग और सेवाओं के लिये यह क्रमशः 11.3% और 7.5% था।
- **बकाया ऋण:** 'ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और भूमिजोत की स्थितिका आकलन, 2019' के आँकड़ों के अनुसार, कृषि परिवारों के ऋण का प्रतिशत वर्ष 2013 के 52% से घटकर वर्ष 2019 में 50.2% हो गया है तथा औसत ऋण 57% से अधिक की वृद्धि के साथ वर्ष 2013 के 47,000 रूपए से बढ़कर वर्ष 2019 में 74,121 रूपए हो गया है।
  - सर्वेक्षण के आँकड़ों से पता चलता है कि कृषि परिवारों द्वारा बकाया ऋण का 69.6% संस्थागत स्रोतों जैसे बैंकों, सहकारी समितियों और अन्य सरकारी एजेंसियों से लिया गया था।
  - यह सर्वेक्षण [राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय](#) (NSO) द्वारा किया जाता है।
- **कृषि ऋण माफी:** चुनावों के आसपास राज्यों द्वारा कृषि ऋण माफी की घोषणा से ऋण देने की पद्धति में विसंगतियाँ उत्पन्न होती हैं।
  - वर्ष 2014 के बाद से, कम से कम 11 राज्यों द्वारा कृषि ऋण माफी की घोषणा की गई है। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।
  - उत्तर प्रदेश सरकार कृषि ऋण पर रियायती ब्याज दरों, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ-साथ [केंद्र के कृषि अवसंरचना कोष](#) (Agriculture Infrastructure Fund) के तहत कृषि बुनियादी ढाँचे के विकास हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी।
    - कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर (Post-Harvest Management Infrastructure) और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम अवधि के ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करना है।
  - वर्ष 2021 में सात राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बैंकों के बीच यह चर्चा बनी हुई है कि इसके चलते कृषि क्षेत्र में NPAs में वृद्धि हो सकती है।
    - जबकि वास्तविक कठिनाई का एक कारण ऋणों की वापसी में हुई देरी हो सकता है। सरकार द्वारा ऋणों में छूट की घोषणा भी बैंकों के समक्ष वसूली में चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकता है।

### ■ चुनौतियाँ:

- **फंड की उपलब्धता:** 'परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी' की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता 'गैर-निष्पादित संपत्ति' की व्यापक मात्रा के साथ संतुलित करने हेतु पर्याप्त धन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
  - यह एक स्वागतयोग्य कदम होगा यदि सरकार अपने पूंजी आधार को मजबूत करने हेतु सरकार एवं 'भारतीय रज़िर्व बैंक' (RBI) के इक्विटी योगदान के साथ ARC की स्थापना करती है।
  - इस प्रकार ARC के पास NPA की गंभीर समस्या से निपटने के लिये पर्याप्त धन होगा।
- **एक जीवंत संकटग्रस्त ऋण बाज़ार की अनुपस्थिति:** भले ही ARC के पास पर्याप्त धन उपलब्ध हो, कति गैर-निष्पादित परिसंपत्ति को खरीदने एवं बेचने के बीच असंतुलित मूल्य और खराब संपत्तियों के स्वीकार्य मूल्यंकन पर समझौता भी ARC के लिये एक चुनौती पैदा करेगा।
  - यह भारत में एक जीवंत संकटग्रस्त ऋण बाज़ार की अनुपस्थिति है। ऐसे में गैर-निष्पादित संपत्तियों को बाज़ार में बेचना भी मुश्किल है।
- **व्यावसायिक विशेषज्ञता का अभाव:** एआरसी में बदलाव के लिए पेशेवर विशेषज्ञता का अभाव एक व्यापक समस्या है।
  - ARCs में शामिल होने वाले बैंकर, वकील और चार्टर्ड एकाउंटेंट जैसे पेशेवर आमतौर पर कुछ अतिरिक्त रटिर्न की उम्मीद करते हैं।
  - हालाँकि, नियामक मुद्दों के कारण यह आसान नहीं है और ARCs पेशेवरों की विशेषज्ञता की सेवा से वंचित हैं जो इसकी काफी मदद कर सकता है।



- **परपिकव द्वितीयक बाज़ार का अभाव:** अर्हताप्राप्त संस्थागत खरीदारों को ARCस द्वारा जारी सुरक्षा रसीदों (SR) हेतु परपिकव द्वितीयक बाज़ार का अभाव है।
  - यह बैंकों को अपनी स्वयं की तनावग्रस्त संपत्तियों द्वारा समर्थित SR खरीदने के लिये प्रेरित करता है।
  - यह देखा गया है कि वर्तमान में 80% से अधिक SR केवल विकिरेता बैंकों के पास ही हैं।
- **नियामक बाधाएँ:** वर्तमान में सभी ARCस, नियामक यानी रज़िर्व बैंक के वनियिमन के अधीन हैं और यह देखा गया है कि कुछ कड़े नयिमों ने उनकी वृद्धि और व्यवहार्यता को बाधित किया है। इस प्रकार, ARCस अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं।

## कृषि क्षेत्र के NPAs से नपिटने हेतु वर्तमान तंत्र:

- वर्तमान में, कृषि क्षेत्र में NPAs से नपिटने के लिये न तो एक एकीकृत तंत्र है और न ही एक भी कानून है।
- कृषि एक राज्य का वषिय होने के कारण, वसूली कानून, जहाँ कहीं भी कृषि भूमि को संपार्षविक के रूप में पेश किया जाता है- अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होते हैं।
- गरिवी रखी गई कृषि भूमि का वनियिमन प्रायः राज्यों के राजस्व वसूली अधिनियम, ऋण की वसूली एवं दवालयिपन अधिनियम, 1993 तथा अन्य राज्य-वशिषिट नयिमों के माध्यम से किया जाता है।
- इनमें अक्सर समय लगता है और कुछ राज्यों में तो बैंक ऋणों को कवर करने वाले राजस्व वसूली कानून लागू भी नहीं किये गए हैं।

## आगे की राह

- बैंकों और ARCस के बीच मूल्य निर्धारण हेतु एक कठोर और यथार्थवादी दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक है।
  - इसलिये NPA बकिरी, समाधान और वसूली की पूरी प्रक्रिया को तेज़ और सुचारू बनाने के लिये नियामक सहित सभी हतिधारकों को एक साथ आने की तत्काल आवश्यकता है।
- कृषि क्षेत्र में करज की वसूली की बात आती है तो बैंकों के हाथ बँधे होते हैं। प्रत्याशति कृषि ऋण माफी की समस्या भी काफी गंभीर है, जिससे वसूली मुश्किल हो जाती है।
- वर्तमान परदृश्य में ARC की बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका है और इसे भारतीय बैंकिंग उद्योग में व्याप्त बड़े पैमाने पर एनपीए की समस्या को हल करने के लिये मज़बूत किया जाना चाहिये।
- हालाँकि, ARC को एकमात्र वधिके रूप में नहीं देखा जा सकता है। सबसे कुशल तरीका यह होगा कि भारत की 'बैड लोन' की समस्या के वभिन्न हसिसों के लिये समाधान तैयार किया जाए और अन्य सभी तरीकों के विकल होने पर केवल अंतमि उपाय के रूप में ARC का उपयोग किया जाए।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

## प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना

### प्रलिमिस के लिये:

PM-SYM, मडि डे मील योजना, कर्मचारी राज्य बीमा नगिम

### मेन्स के लिये:

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मज़दूरों हेतु सरकारी योजनाएँ

## चर्चा में क्यों?

श्रम और रोज़गार मंत्रालय के अनुसार, [प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन \(PM-SYM\) पेंशन योजना](#) के तहत लगभग 46 लाख [असंगठित श्रमिकों \(Unorganised Workers\)](#) का पंजीकरण किया गया है।

## असंगठित श्रमिक (Unorganised Worker)

- असंगठित श्रमिकों में प्रमुख रूप से रकिशा चालक, स्ट्रीट वेंडर्स, [मडि डे मील श्रमिक](#), हेड लोडर, ईट भट्टा श्रमिक, मोची, कचरा उठाने वाले,

घरेलू कामगार, धोबी, घर से काम करने वाले श्रमिक, स्व-कर्मचारी, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, ऑडियो-वीडियो श्रमिक या इसी तरह के अन्य व्यवसायों में कार्यरत लोगों को शामिल किया जाता है।

■ देश में ऐसे वर्गों में शामिल असंगठित श्रमिकों की संख्या 45 करोड़ अनुमानित है।

## प्रमुख बंदि:

### ■ परिचय:

- PM-SYM श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है और भारतीय जीवन बीमा निगम तथा **सामुदायिक सेवा केंद्रों (CSC)** के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
  - **जीवन बीमा निगम (LIC)** पेंशन फंड मैनेजर (Pension Fund Manager) होगी और पेंशन भुगतान के लिये उत्तरदायी होगी।

### ■ पात्रता:

- एक असंगठित श्रमिक (UW) होना चाहिये।
- मासिक आय 15000 रुपए या उससे कम।
- प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच।
- मोबाइल फोन, बचत बैंक खाता और आधार नंबर होना चाहिये।
- **नई पेंशन योजना (NPS)**, **कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)** और **कर्मचारी भविष्य नधि संगठन (EPFO)** के लाभ के अंतर्गत कवर न किया गया हो।
- आयकर दाता नहीं होना चाहिये।

### ■ प्रमुख विशेषताएँ:

#### ○ न्यूनतम नश्चिति पेंशन (Minimum Assured Pension):

- PM-SYM के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को **60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रतिमहीने न्यूनतम 3,000 रुपए की नश्चिति पेंशन** मिलेगी।

#### ○ परिवार को पेंशन (Family Pension):

- यदि पेंशन प्राप्तिके दौरान **अभिदाता (subscriber)** की मृत्यु हो जाती है तो **लाभार्थी को मिलने वाली पेंशन की 50 प्रतिशत राशि फ़ैमिली पेंशन के रूप में लाभार्थी के जीवनसाथी (Spouse)** को मिलेगी।
- यदि लाभार्थी ने नियमि अंशदान किया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु (60 वर्ष की आयु से पहले) हो जाती है तो लाभार्थी का जीवनसाथी योजना में शामिल होकर नियमि अंशदान करके योजना को जारी रख सकता है या योजना से बाहर निकलने और वापसी के प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकल सकता है।

#### ○ अंशदान:

- अभिदाता का अंशदान उसके **बचत बैंक खाता/जनधन खाता से 'ऑटो डेबिट' (auto-debit) सुविधा** के माध्यम से किया जाएगा।
- PM-SYM **50:50 के अनुपात** के आधार पर एक स्वैच्छिक तथा अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें निर्धारित आयु विशेष अंशदान (Age-Specific Contribution) लाभार्थी द्वारा किया जाएगा और जमा राशिके अनुसार बराबर का अंशदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

### ■ असंगठित क्षेत्र के लिये अन्य सरकारी योजनाएँ:

- [श्रम सुधार](#)
- [प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना \(PMRPY\)](#)
- [पीएम स्वनधि: स्ट्रीट वेंडर्स हेतु माइक्रो क्रेडिट स्कीम](#)
- [आत्मनिर्भर भारत अभियान](#)
- [दीनदयाल अंतयोदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मशिन](#)
- [प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना \(PMGKAY\)](#)
- [एक राष्ट्र एक राशन कार्ड](#)
- [आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना](#)
- [प्रधानमंत्री किसान सममान नधि](#)
- [भारत के अनौपचारिक मजदूर वर्ग को विश्व बैंक का समर्थन](#)

स्रोत: पी.आई.बी.

देशद्रोह कानून

# प्रलिम्स के लिये

IPC की धारा 124A

## मेन्स के लिये

देशद्रोह कानून और संबंधित मुद्दे

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में असम पुलिस द्वारा असम के असमिया और बंगाली भाषी लोगों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिये एक पत्रकार पर [देशद्रोह](#) का आरोप लगाया गया था।

### प्रमुख बिंदु

#### ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- राजद्रोह कानून को 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में अधिनियमित किया गया था, उस समय वधिनिर्माताओं का मानना था कि सरकार के प्रति अच्छी राय रखने वाले वधिचारों को ही केवल असतत्त्व में या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना चाहिये, क्योंकि गलत राय सरकार और राजशाही दोनों के लिये नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती थी।
- इस कानून का मसौदा मूल रूप से वर्ष 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन वर्ष 1860 में [भारतीय दंड संहिता](#) (IPC) लागू करने के दौरान इस कानून को IPC में शामिल नहीं किया गया।
- वर्तमान में [राजद्रोह कानून की स्थिति](#): भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A के तहत राजद्रोह एक अपराध है।

#### वर्तमान में राजद्रोह कानून

##### IPC की धारा 124A

- यह कानून राजद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित करता है जिसमें 'किसी व्यक्ति द्वारा भारत में कानूनी तौर पर स्थापित सरकार के प्रति भौखिक, लिखित (शब्दों द्वारा), संकेतों या दृश्य रूप में घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है।
- वद्रोह में वैमनस्य और शत्रुता की सभी भावनाएँ शामिल होती हैं। हालाँकि इस खंड के तहत घृणा या अवमानना फैलाने की कोशिश किये बिना की गई टिप्पणियों को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है।
- राजद्रोह के अपराध हेतु दंड**
  - राजद्रोह गैर-जमानती अपराध है। राजद्रोह के अपराध में तीन वर्ष से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा हो सकती है और इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
  - इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त करने से रोका जा सकता है।
    - आरोपित व्यक्ति को पासपोर्ट के बिना रहना होता है, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उसे न्यायालय में पेश होना ज़रूरी है।

#### राजद्रोह कानून का महत्त्व:

##### उचित प्रतिबंध:

- भारत का संविधान उचित प्रतिबंध ([अनुच्छेद 19\(2\)](#) के तहत) निर्धारित करता है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रति ज़िम्मेदार अभ्यास को सुनिश्चित करता है साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि **किसी भी नागरिकों के लिये समान रूप से उपलब्ध** है।

##### एकता और अखंडता बनाए रखना:

- राजद्रोह कानून सरकार को **राष्ट्र-विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्त्वों का मुकाबला करने में मदद** करता है।

##### राज्य की स्थिरता को बनाए रखना:

- यह चुनी हुई सरकार को **हिसा और अवैध तरीकों से सरकार को उखाड़ फेंकने के प्रयासों से बचाने में मदद** करता है। कानून द्वारा स्थापित सरकार का निरंतर असतत्त्व राज्य की स्थिरता के लिये एक अनविरय शर्त है।

#### राजद्रोह कानून से संबंधित मुद्दे:

##### औपनिवेशिक युग का अवशेष:

- औपनिवेशिक प्रशासकों ने **ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने वाले लोगों को रोकने के लिये** राजद्रोह कानून का इस्तेमाल किया।
- लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह** आदि जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के दगिगजों को ब्रिटिश शासन के तहत उनके "राजद्रोही" भाषणों, लेखन और गतिविधियों के लिये दोषी ठहराया गया था।
- इस प्रकार राजद्रोह कानून का इतना व्यापक उपयोग औपनिवेशिक युग की याद दिलाता है।

##### संविधान सभा का रूख:

- संविधान सभा **संविधान में राजद्रोह को शामिल करने के लिये सहमत नहीं** थी। सदस्यों का तर्क था कि यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करेगा।
- उन्होंने तर्क दिया कि **लोगों के विरोध के वैध और संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार को दबाने के लिये राजद्रोह कानून को एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा सकता है।**

##### सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की अवहेलना:

- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1962 में **केदार नाथ सहि बनाम बहिर राज्य मामले** में धारा 124A की संवैधानिकता पर अपना नरिणय दधिया । इसने देशद्रोह की संवैधानिकता को बरकरार रखा लेकनल इसे अव्यवस्था पैदा करने का इरादा, कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी तथा हसल के लयल उकसाने की गतवधलधलयों तक सीमलत कर दधिया ।
- इस प्रकार, शकलषावदलँ, वकलयँ, सामाजकल-राजनीतकल कारयकरतताओं और छातरँ के खलललफ देशद्रोह का आरोप लगाना सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है ।
- **लोकतांतरकल मूलयँ का दमन:**
  - भारत को तेजी उभरते एक नरलवाचतल नरलकुश राज्य के रूप में वर्णतल कयल जा रहा है, मुख्य रूप से राजद्रोह कानून के कठोर और गणनात्मक उपयोग के कारण ।
- **हालया वकलस:**
  - **फरवरी 2021** में **सर्वोच्च न्यायालय** (Supreme Court) ने एक राजनीतकल नेता और छह वरषलठ पत्रकारों को उनके खलललफ दरज राजद्रोह के कई मामलों में गरलफतारी से संरकषण प्रदान कयल है ।
  - **जून 2021** में, सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दो तेलुगु (भाषा) समाचार चैनलों को जबरदस्ती कार्रवाई से संरकषण प्रदान करते हुए राजद्रोह की सीमा को परलभाषतल करने पर ज़ोर दधया ।
  - **जुलाई 2021** में, सर्वोच्च न्यायालय में एक याचकल दायर की गई थी, जसलमें देशद्रोह कानून पर फरल से वधलार करने की मांग की गई थी ।
    - न्यायालय ने कहा, "सरकार के प्रतल असंतोष" की असंवैधानकल रूप से असुपषुट परलभाषाओं के आधार पर स्वतंत्र अभवलयकतल कल अपराधीकरण करने वाला कोई भी कानून **अनुच्छेद 19 (1) (अ)** के तहत गारंटीकृत अभवलयकतल की स्वतंत्रता के मौलकल अधकलार पर अनुचतल प्रतलबंध है और संवैधानकल रूप से अनुमेय भाषण पर 'दुरुतशीतन प्रभाव' (Chilling Effect) का कारण बनता है ।

## आगे की राह:

- IPC की धारा 124A की उपयोगतल राष्ट्रवरलधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्त्वों से नपलटने में है । हालाँकल, सरकार के नरलणयों से असहमतल और आलोचना एक जीवंत लोकतंत्र में मज़बूत सार्वजनकल बहस का आवश्यक तत्त्व है । इन्हें देशद्रोह के रूप में नहीं देखा जाना चाहयल ।
- उच्च न्यायपालकल को अपनी परयवेकषी शकतलयँ का उपयोग मजसलटरेट और पुलसल को अभवलयकतल की स्वतंत्रता की रकषा करने वाले संवैधानकल प्रावधानों के प्रतल संवेदनशील बनाने हेतु करना चाहयल ।
- राजद्रोह की परलभाषा को केवल भारत की कषेत्रीय अखंडता के साथ-साथ देश की संपरभुता से संबंधतल मुद्दों को शामिल करने के संदर्भ में संकुचतल कयल जाना चाहयल ।
- देशद्रोह कानून के मनमाने इस्तेमाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के ललए नागरकल समाज को पहल करनी चाहयल ।
- भारत वशलव का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अभवलयकतल की स्वतंत्रता का अधकलार लोकतंत्र का एक अनवरार्य घटक है जो अभवलयकतल या वधलार उस समय की सरकार की नीतल के अनुरूप नहीं हो उसे देशद्रोह नहीं माना जाना चाहयल ।
- देशद्रोह' शब्द अतयंत संवेदनशील है और इसे सावधानी के साथ लागू करने की आवश्यकता है ।

## स्रोत: द हदू

## बाँध सुरकषा वधलयक, 2019

### प्रलमलस के लयल:

केंद्रीय जल आयोग, बाँध सुरकषा वधलयक, 2019, राष्ट्रीय बाँध सुरकषा प्राधकलरण

### मेन्स के लयल:

बाँध सुरकषा वधलयक, 2019 की प्रमुख वशलषताएँ, इसकी आवश्यकता एवं महत्त्व

## चर्चा में कयल?

हाल ही में संसद ने देश भर में सभी नरलदषलट बाँधों की नगरलनी, नरलकषण, परचालन और रखरखाव के लयल **बाँध सुरकषा वधलयक, 2019** को मंजूरी दे दी है ।

## प्रमुख बलदु

- वधलयक की मुख्य वशलषताएँ:
  - **राष्ट्रीय बाँध सुरकषा समतल:** वधलयक राष्ट्रीय बाँध सुरकषा समतल की स्थापना का प्रावधान करता है । समतल की अध्यक्षतल **केंद्रीय**



**जल आयोग** के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

- **समिति के कार्यों** में बाँध सुरक्षा मानदंडों से संबंधित नीतियाँ एवं वनियम बनाना तथा बाँधों को क्षतगिरस्त होने से रोकना एवं बड़े बाँधों के टूटने के कारणों का विश्लेषण करना एवं बाँध सुरक्षा प्रणालियों में बदलाव का सुझाव देना शामिल होगा।
- **राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण:** वधियक एक **राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण (National Dam Safety Authority -NDSA)** की स्थापना का प्रावधान करता है। इस प्राधिकरण का प्रमुख एडिशनल सेक्रेटरी से नीचे के स्तर का अधिकारी नहीं होगा एवं इसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
  - **राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण** के मुख्य कार्य में **राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा समिति** द्वारा निर्मित नीतियों को लागू करना शामिल है। राज्य बाँध सुरक्षा संगठनों (SDSOs) के बीच और SDSOs एवं उस राज्य के किसी बाँध मालिक के बीच विवादों को सुलझाना, बाँधों के नरीक्षण और जाँच के लिये वनियम को नरिदष्टि करना।
  - NDSA बाँधों के नरिमाण, डज़िाइन तथा उनमें परिवर्तन पर काम करने वाली एजेंसियों को मान्यता (Accreditation) देगी।
- **राज्य बाँध सुरक्षा संगठन:** प्रस्तावित कानून में राज्य सरकारों द्वारा राज्य बाँध सुरक्षा संगठनों (State Dam Safety Organisation- SDSOs) की स्थापना की जाएगी जिसका कार्य बाँधों की नरितर चौकसी एवं नरीक्षण करना तथा उनके परिचालन एवं रखरखाव पर नगरानी रखना, सभी बाँधों का डेटाबेस रखना और बाँध मालिकों को सुरक्षा उपायों की सफ़ारिश करना होगा।
- **बाँध मालिकों की दायित्व:** वधियक में नरिदष्टि बाँध मालिकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे **प्रत्येक बाँध के लिये एक सुरक्षा इकाई** स्थापित करे। यह इकाई मानसून सत्र से पहले और बाद में एवं प्रत्येक भूकंप, बाढ़, या किसी अन्य आपदा या संकट के संकेत के दौरान और बाद में बाँधों का नरीक्षण करेगी।
  - बाँध मालिकों से **एक आपातकालीन कार्ययोजना तैयार करने** और प्रत्येक बाँध के लिये **नरिदष्टि अंतराल पर नयिमति जोखिम आकलन करने की अपेक्षा** की जाएगी।
  - बाँध मालिकों द्वारा नयिमति अंतराल पर एक विशेषज्ञ पैनल के जरिये प्रत्येक बाँध का व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन किया जाएगा।
- **सज़ा:** वधियक में **दो प्रकार के अपराधों** का उल्लेख है- किसी व्यक्ति को उसके कार्यों के नरिवहन में बाधा डालना और प्रस्तावित कानून के अंतर्गत जारी नरिदेशों के अनुपालन से इनकार करना।
  - अपराधियों को **एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।** अगर अपराध के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है तो कारावास की अवधि दो वर्ष हो सकती है।
  - अपराध संज्ञेय तभी होंगे जब **शकियत सरकार द्वारा या वधियक के अंतर्गत गठित किसी प्राधिकरण** द्वारा की जाए।

#### ■ आवश्यकता

- **बाँधों का कालिक कषय:**
  - बाँधों की संख्या के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। देश में 5,745 जलाशय हैं जिनमें से 293 जलाशय 100 साल से अधिक पुराने हैं। बाँध सुरक्षा के लिये कई चुनौतियाँ हैं और कुछ मुख्य रूप से बाँधों की लंबी उम्र के कारण हैं।
  - जैसे-जैसे बाँध पुराने होते जाते हैं, उनका डज़िाइन, जल वज़िाजान और बाकी सब कुछ नवीनतम समझ और प्रथाओं के अनुरूप नहीं रहता है।
  - बाँधों में भारी गाद जमा होती जाती है जिससे इनकी जल धारण क्षमता कम होती जा रही है।
- **बाँध प्रबंधकों पर नरिभरता:**
  - बाँधों का वनियमन पूरी तरह से व्यक्तिगत बाँध प्रबंधकों पर नरिभर है। डाउनस्ट्रीम जल की आवश्यकता या पहले से मौजूद प्रवाह के प्रकार के संदर्भ में कोई व्यवस्थितिकरण और कोई वास्तविक समझ नहीं है।
- **वभिन्न कारकों पर वचिार नहीं किया जाना:**
  - बाँध सुरक्षा कई कारकों पर नरिभर है जैसे कि भूदृश्य, भूमि उपयोग परिवर्तन, वर्षा के पैटर्न, संरचनात्मक विशेषताएँ आदि। बाँध की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार द्वारा सभी कारकों को ध्यान में नहीं रखा गया है।
- **बाँधों की वफिलताएँ:**
  - उचित बाँध सुरक्षा संस्थागत ढाँचे के अभाव में बाँधों की जाँच, डज़िाइन, नरिमाण, संचालन और रखरखाव में वभिन्न प्रकार की कमियाँ शामिल हो सकती हैं। इस तरह की कमियों से गंभीर घटनाएँ होती हैं और कभी-कभी बाँध टूट जाता है।
  - वर्ष 1917 में तगिरा बाँध (मध्य प्रदेश) की वफिलता के साथ बाँधों की वफिलताओं की शुरुआत हुई और अब तक लगभग 40 बड़े बाँधों के वफिल होने की सूचना है। नवंबर 2021 में अन्नामय्या बाँध (आंध्र प्रदेश) की वफिलता का सबसे हालिया मामला 20 लोगों की मौत का कारण बना है।
  - सामूहिक रूप से इन वफिलताओं के चलते हज़ारों मौतें और विशाल आर्थिक नुकसान देखने को मिला है।

#### ■ महत्त्व:

- **एकरूपता लाना:**
  - सरकार चाहती है कि एक विशेष प्रकार के बड़े बाँधों के लिये सभी बाँध मालिकों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं में एकरूपता हो।
- **सख्त दशा-नरिदेश प्रदान करता है:**
  - पानी, राज्य का वषिय है और यह वधियक किसी भी तरह से राज्य के अधिकार को नहीं छिनता है। वधियक दशा-नरिदेशों को सुनिश्चित करने के लिये एक तंत्र प्रदान करता है।
  - इसमें बाँध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये पूरी व पोस्ट-मानसून नरीक्षण सहित कई प्रोटोकॉल हैं। हालाँकि अब तक ये प्रोटोकॉल कानूनी रूप से अनविर्य नहीं हैं और संबंधित एजेंसियों (केंद्रीय एवं राज्य बाँध सुरक्षा संगठनों सहित) के पास इन्हें लागू करने की कोई शक्ति नहीं है।
- **गुणवत्ता सुनिश्चित करना:**
  - अब तक वभिन्न ठेकेदारों, डज़िाइनरों और योजनाकारों की व्यावसायिक दक्षता का मूल्यांकन कभी नहीं किया गया है और यही कारण है कि आज भारत के बाँधों में डज़िाइन की समस्या है। वधियक एक ऐसा तंत्र प्रदान करता है जहाँ नरिमाण और रखरखाव में भाग लेने वाले लोगों को ध्यान में रखा जाना चाहिये।
- **सुरक्षा:**

- बाँधों के क्षतग्रस्त होने का खतरा हमेशा बना रहता है और इसलिए उनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। वधियक में बाँध सुरक्षा मानकों के निर्माण का प्रावधान है।

#### ■ चर्चा:

##### ○ वसिगत:

- केंद्रीय जल आयोग सभी बाँध परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिये ज़िम्मेदार होगा। इसे उसी परियोजना (यदि परियोजना विफल हो जाती है) का ऑडिट करने का भी अधिकार है।
- यह अपने मामले में स्वयं न्यायाधीश के रूप में कार्य करने जैसा है।

##### ○ क्षतपूरत पर नरुत्तर:

- बाँध परियोजनाओं से प्रभावित लोगों को क्षतपूरत के लिये भुगतान पर वधियक नरुत्तर है।

##### ○ संघीय ढाँचे में हस्तक्षेप:

- राज्यों ने आरोप लगाया कि यह असंवैधानिक है इसलिये इसकी जाँच की जानी चाहिये क्योंकि और राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है। वधियक के कुछ प्रावधान [संघीय ढाँचे](#) में हस्तक्षेप करते हैं।

## वधियक की संवैधानिक वैधता

- हालीक जल को राज्य सूची की प्रवर्षिट-17 में रखा गया है, केंद्र ने संवधान के अनुच्छेद 246 के तहत संघ सूची की प्रवर्षिट 56 और प्रवर्षिट 97 के साथ कानून प्रस्तुत किया है।
  - **राज्य सूची, प्रवर्षिट 17:** जल, अर्थात् जल आपूर्त, सचिई और नहरें, जल निकासी एवं तटबंध, जल भंडारण व जल शक्तसूची। की प्रवर्षिट 56 के प्रावधानों के अधीन है।
  - **सूची। की प्रवर्षिट, 56** संसद को अंतर-राज्यीय नदियों व नदी घाटियों के नियमन पर कानून बनाने की अनुमति देती है जो इस तरह के विनियमन को सार्वजनिक हित में समीचीन घोषित करती है।
- **अनुच्छेद 246** संसद को संवधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची की सूची। में सूचीबद्ध किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है।
- प्रवर्षिट 97 संसद को सूची II या सूची III में सूचीबद्ध किसी भी अन्य मामले पर कानून बनाने की अनुमति देता है, जिसमें कर सहित उन सूचियों में से किसी में भी उल्लेख नहीं किया गया है।

## आगे की राह

- चूँकि बाँध की सुरक्षा कई बाहरी कारकों पर निर्भर है, इसलिये पर्यावरणविदों और पर्यावरण के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाना चाहिये [बदलती जलवायु](#) के साथ पानी के मुद्दे पर सावधानीपूर्वक और सटीक रूप से विचार करना आवश्यक है।
- राज्य के सचिई विभाग और केंद्रीय जल आयोग को मज़बूत करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि बाँधों का निरीक्षण संबंधित राज्य की सरकार करे।
- बाँधों के मामले में विफलताओं से बचने के लिये एक निवारक तंत्र आवश्यक है क्योंकि यदि बाँध निर्माण के उद्देश्यों में विफलता प्राप्त होती है तो कतिनी बड़ी सज़ा क्यों न दी जाए वह जीवन के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती है।

## स्रोत: द हट्टू

## भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण

### प्रलिमिस के लिये:

सर्वोच्च न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय वधिक सेवा प्राधिकरण

### मेन्स के लिये:

राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण की आवश्यकता

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में, [भारत के मुख्य न्यायाधीश](#) द्वारा **भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (National Judicial Infrastructure**

Authority of India- NJIAI) के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है।

## प्रमुख बिंदु

### ■ राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (NJIAI):

#### ○ राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण के बारे में:

- प्रस्तावित NJIAI एक केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, जिसमें [राष्ट्रीय वधिक सेवा प्राधिकरण](#) (NALSA) मॉडल की तरह प्रत्येक राज्य का अपना राज्य न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण होगा।
  - NALSA का गठन समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएँ प्रदान करने हेतु एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करने के लिये किया गया था।
- देश में अधीनस्थ न्यायालयों के बजट और बुनियादी ढाँचे के विकास का नियंत्रण NJIAI के अंतर्गत होगा।
- **NALSA (नालसा) जो कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा सेवित है के विपरीत प्रस्तावित NJIAI को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन रखा जाना जाएगा।**
- यह किसी बड़े नीतिगत बदलाव का सुझाव नहीं देगा, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अदालतों को मज़बूती प्रदान करने हेतु चल रही परियोजनाओं में सर्वोच्च न्यायालय को साथ आने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान करेगा।

#### ○ सदस्य:

- NJIAI में कुछ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा कुछ केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल होंगे क्योंकि केंद्र को यह भी मालूम होना चाहिये कि धन का उपयोग कहाँ किया जा रहा है।
- इसी प्रकार राज्य न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त एक मनोनीत न्यायाधीश, चार से पाँच ज़िला न्यायालय के न्यायाधीश तथा राज्य सरकार के अधिकारी सदस्य शामिल होंगे।

### ■ NJIAI की आवश्यकता:

#### ○ नधियों का प्रबंधन करने के लिये:

- न्यायालयों में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये **केंद्र प्रायोजित योजना (CSS)** के तहत वर्ष 2019-20 में स्वीकृत कुल 981.98 करोड़ रुपए में से केवल 84.9 करोड़ रुपए ही पाँच राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से उपयोग में लाए गए, शेष 91.36% धन अप्रयुक्त रहा।
  - भारतीय न्यायपालिका के साथ लगभग तीन दशकों (जब 1993-94 में CSS को पेश किया गया था) से यह मुद्दा बना हुआ है।

#### ○ मुकदमों की बढ़ती संख्या को प्रबंधित करने के लिये:

- भारतीय न्यायपालिका का बुनियादी ढाँचा हर साल दायर होने वाले मुकदमों की बढ़ी संख्या के साथ तालमेल नहीं रखता है।
  - इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि देश में न्यायिक अधिकारियों की कुल स्वीकृत संख्या 24,280 है, लेकिन उपलब्ध न्यायालय कक्षाओं की संख्या केवल 20,143 है, जिसमें 620 करिए के हॉल शामिल हैं।

#### ○ बृहत्तर स्वायत्तता के लिये:

- न्यायिक बुनियादी ढाँचे का सुधार और रख-रखाव अभी भी तदर्थ और अनियोजित तरीके से किया जा रहा है।
  - इस हेतु "न्यायपालिका की वित्तीय स्वायत्तता" और NJIAI (जो एक केंद्रीय एजेंसी के रूप में स्वायत्तता के साथ काम करेगी) के निर्माण की आवश्यकता है।

### ■ अवसंरचनात्मक रूप से पीछे रहने के कारण:

#### ○ वित्त की कमी:

- न्यायिक बुनियादी ढाँचे को विकसित करने के लिये, केंद्र सरकार और राज्यों द्वारा न्यायपालिका के बुनियादी ढाँचे संबंधी विकास हेतु **केंद्र प्रायोजित योजना**, जिसकी शुरुआत वर्ष 1993 में हुई और जुलाई 2021 में अगले पाँच वर्षों के लिये बढ़ा दिया गया था।
- हालाँकि राज्य अपने हिससे का धन उपलब्ध नहीं कराते हैं जिसके परिणामस्वरूप, उनके द्वारा योजना के तहत आवंटित धन का व्यय नहीं हो पाता है और यह व्ययगत हो जाता है।

#### ○ गैर-न्यायिक उद्देश्यों के लिये नधियों का उपयोग:

- कुछ मामलों में, राज्यों द्वारा यह दावा किया गया है कि उन्होंने गैर-न्यायिक उद्देश्यों के लिये फंड का हिस्सा भी स्थानांतरित किया है।
  - यहाँ तक कि न्यायपालिका, विशेष रूप से नचिली अदालतों में, कोई भी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है।

## भारत में न्यायपालिका से संबद्ध मुद्दे

### ■ देश में न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात बहुत प्रशंसनीय नहीं है।

- जबकि अन्य देशों में, यह अनुपात लगभग 50-70 न्यायाधीश प्रति मिलियन व्यक्ति है, भारत में यह अनुपात 20 न्यायाधीश प्रति मिलियन व्यक्ति है।

### ■ महामारी के बाद से ही न्यायालयी कार्यवाही भी वस्तुतः होने लगी है, पहले न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी की भूमिका ज़्यादा बढ़ी नहीं थी।

### ■ न्यायपालिका में पदों को आवश्यकतानुसार शीघ्रता से नहीं भरा जाता है।

- उच्च न्यायपालिका के लिये **कॉलेजियम** द्वारा की जाने वाली सफ़ारिशों में देरी के कारण न्यायिक न्युक्ति की प्रक्रिया में देरी होती है।
- नचिली अदालतों के लिये राज्य आयोग/उच्च न्यायालयों द्वारा भरती में होने वाली देरी भी खराब न्यायिक व्यवस्था का एक कारण है।

### ■ अदालतों द्वारा अधिवक्ताओं को बार-बार स्थगन दिया जाता है जिससे न्याय में अनावश्यक देरी होती है।

## आगे की राह

- भारत में न्यायालयों द्वारा बार-बार व्यक्तियों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता को बरकरार रखा गया है और ये व्यक्तियों या समाज के साथ उस स्थिति में भी खड़ी रही हैं जब कार्यपालिका द्वारा लिये गए फैसलों का दुष्प्रभाव उन पर पड़ा हो।
- यदि हम न्यायिक प्रणाली से भिन्न परिणाम चाहते हैं, तो हम इन परिस्थितियों में काम करना जारी नहीं रख सकते।
- **आज़ादी के इस 75 वें वर्ष** में अपनी जनता और अपने देश को अत्याधुनिक न्यायिक अवसंरचना के सृजन और उसे आगे बढ़ाने हेतु तंत्र/प्रक्रियाओं को संस्थागत बनाना सबसे अच्छा उपहार हो सकता है।
- CSS योजना पूरे देश में ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के लिये सुसज्जित कोर्ट हॉल और आवास की उपलब्धता में वृद्धि करेगी।
- डिजिटल कंप्यूटर रूम की स्थापना से डिजिटल क्षमताओं में भी सुधार होगा और भारत के **डिजिटल इंडिया विज़न** के एक हिस्से के रूप में डिजिटलीकरण की पहल को बढ़ावा मिलेगा।

## स्रोत: द द्रिष्टि

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/06-12-2021/print>

